हैं उनको कार्टिजेज मिलती है। आज भी मक्का और मदीना से लोग एयर गन्स लेकर आ रहे हैं। अब एयर गन्स के कारतूस से किसी को नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन मुझे जानकारी है कि उनके लिए इंडिजिनस वे में कार्टिजेज बनाई जाती है जिनसे आदमी तो क्या अच्छे से जानवर की भी हत्या हो सकती है। उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है और लाखों की संख्या में हिन्दुस्तान में एयर गन्स हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी इंडिजिनस वे में उनके लिए कार्टिजेस बन रही हैं और वह उसमें काम आ रही हैं। यह जो खतरनाक स्थिति देश में बन रही है उस दृष्टि से म सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस हिंसा के वातावरण को रोकना है तो जो हथियारों का स्मगलिंग होकर बाहर से देश में आ रहे हैं उनको रोका जाए और इस प्रकार की इल्लीगल मनुफैक्चरिंग जो चल रही है उनको जल्दी से जल्दी रोका जा और उनको रोकने के लिए आर्म्स ऐक्ट में संशोधन किया जाए और जिन लोगों के पास अंडरग्राउंड हथियार हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। 1965 में राजस्थान के अन्दर बार्डर के ऊपर जिन लोगों के पास अनधिकृत हथियार थे, मैंने उस समय सरकार को सुझाव दिया कि अंडर ग्राउंड हथियारों को अगर निकालना है तो एक बार आप इजाजत दे दीजिए कि सब रजिस्ट्रेशन हथियारों का करा लें। गवर्नमेंट ने परमिशन दी और हजारों हथियार जो अंडरग्राउंड थे वह सारे के सारे रजिस्ट्रर हो गये और जो राजस्थान की सीमा पर डाकू लोग थे उनकी डकैती की प्रवृत्तियां भी रुक गई। सरकार यह भी पसन्द करती है कि जिनके पास हमारे बने हुए हथियार हैं जो अंडरग्राउंड चले गये तो उनको बाहर निकालने के लिए यदि रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में किसी प्रकार की लीनियेंसी या रिलीफ दी जाए तो वह भी एक प्रकार का सुझाव होगा जिसको सरकार को कंसिडर करना चाहिए।

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली) : मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये मक्का, मदीना से कैसे जो लोग आते हैं, हथियार ले आते हैं?

श्री भैरो सिंह शेखावत : मेरे कहने का मतलब धार्मिक भावना पर नहीं है लेकिन जो लोग बाहर जाते हैं वह एयर गन्स लाते हैं। एयर गन्स लाने की जो परमिशन दी जाती है वह गलत है, इसको मैं भी और आप भी स्वीकार करेंगे। मक्का मदीना से आने का मतलब यह नहीं है कि मेरा धार्मिक भावना से संबंध है।

REFERENCE TO DROUGHT CONDITIONS IN ORISSA

श्री रबी राय (उड़ीसा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक महत्वपूर्ण सवाल के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो अखबार की खबर है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह है उड़ीसा में दुर्भिक्ष की स्थिति के संबंध म। उड़ीसा के खुद के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं वह कहते हैं—

"Mr. Das, who is also in charge of relief operations. said that there were 60 lakh people in the 1,600 gram panchayats declared drought-affected. The worst-affected areas were Nawapara sub-division of Kalahandi district, Athmallick sub-division of Dhenkanal district, Padmapur sub-division of Sambalpur district, Birmaharajpur sub-division of Balangir district, three blocks of Norrangpur sub-division of Koraput district and the Harbhanga area of Phulbani district."

—फिर मुख्य मंत्री बताते हैं :

"About six lakh people, besides several children and old and infirm persons, who are in acute distress, will have to be provided with work during the next three months."

[श्री रबी राय]

"Talking to newsmen on her return from a visit to the affected areas she said that even big tanks and wells had no water. It was a "pathetic sight".

फिर मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि :

"Stray cholera cases had been reported from the Khariar area."

उपसभाध्यक्षा जी, सवाल यह है कि 60 लाख लोग दुर्भिक्ष से पीड़ित है यह राजस्व मंत्री मान रहे हैं। लेकिन मैंने पिछले नवम्बर में यह सवाल उठाया था कि

Scarcity condition in Orissa is hitting 12 million people.

अब खुद राजस्व मंत्री मान रहे हैं कि 60 लाख से अधिक लोग दुर्भिक्ष से पीड़ित हैं। 6 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है पीने को, खाने को खाना नहीं मिल रहा है ; हमारी यह जानकारी है कि वे लोग हैजे से नहीं मर रहे हैं बल्कि पिछली फरवरी तक 6 की तादाद में भूख से लोग मर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से जो इंतजाम इसके लिये हो रहा है वह काफी नहीं है। मैं आपका ध्यान खीचना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने खुद माना है कि 6 लाख लोग भूक से पीड़ित है और मुख्य मंत्री यह मान रहे हैं कि सिर्फ 7 हजार लोगों के लिए ग्रेटूइस के रिलीफ का इंतजाम किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के एक जिले में 1966 में जिस प्रकार दुर्भिक्ष हुआ था उसी प्रकार का दुर्भिक्ष इस वक्त हुआ है और राज्य सरकार इसको नजर अंदाज कर रही है। इसलिए मैं आपके जरिए भारत सरकार से अनुरोध करुंगा :—

The worst affected areas according to the Revenue Minister were Nawapara sub-division of Kalahandi district, Athmalick sub-division of Dhenkanal district, Padampur sub-division of Sambalpur district, Birmaharajpur sub-division of Balangir district, three blocks of Norrangpur sub-division of Koraput district and Harbhanga area of Phulbani district.

4-5 जिलों में पिछले कई महीनों से लोग भुख से मर रहे हैं। मैं आपके जरिए यह कहना चाहता हूं कि इन सारे इलाकों को दुर्भिक्ष पीड़ित इलाका घोषित किया जाए ताकि सरकार, इन इलाकों में से जो 6 लाख लोग मरने वाले हैं और जब कि राज्य सरकार ने सिर्फ 7-8 हजार लोगों के लिए ग्रेटूइट्स रिलीफ का इंतजाम किया है, 4-5 महीनों के अंदर उनके खाने का इंतजाम और दूसरे इंतजाम कर सके। खुद मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि वहां पर सारे के सारे कुए सूखे पड़े हैं। कोई इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका इंतजाम आपको करना है। यह जो उड़ीसा के 4-6 जिलों में दुर्भिक्ष की स्थिति है भुखमरी की स्थिति है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि राज्य सरकार को जो सहायता दी जाती है उसको देखा जाए और सरकार की ओर से प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य को वहां जाना चाहिए और स्थिति को देखना चाहिए। राज्य सरकार को वह कहे कि इन सारे इलाकों को फैमिन अफैक्टेड इलाके घोषित करे ताकि सारे इलाको में लोगों की भूख से रक्षा की जा सके, भूख से मरने से बचाया जा सके। यही मेरा कहना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The House stands adjuorned till 2.15 P.M. today.

The House then adjourned for lunch at twentyfour minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eighteen minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shrimati Purabi Mukhopadhyay)** in the Chair.

REFERENCE TO ARREST OF SHRI R. K. GARG, TOGETHER WITH SOME WORKERS OF HARDWAR HEAVY ELECTRICALS

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Madam, we are the Council of States. Mr. R. K. Garg, an MLA of the UP Assembly, together with some workers of the Hardwar Heavy Electricals, has been arrested in front of the residence of Mr. T. A. Pai. They were there for starting a hunger-strike in protest against what they call the violation by Mr. T. A. Pai of the assurance the Prime Minister has given to them. Mr. Garg and others when they met them, in regard to the so-colled national sector. The Prime Minister is reported to have told them that there was no proposal for starting the so-called national sector and all that, and that it was only an individual case. Now that Mr. T. A. Pai has made a statement repudiating according to them, what the Prime Minister had told them, in order to register their protest against that kind of thing, what they call the violation by Mr. T. A. Pai of the Prime Minister's assurance, they wanted to start what they called a peaceful test. Why should the Government go and arrest them? He is an MLA and a very well-known advocate of the Supreme Court, well known to everybody. I would ask Mr. Om Mehta to tell us—he was not going there for violating any law—what was the need for the Government to go and arrest him and other workers there in front of Mr. T. A. Pai's house.

If this kind of misuse of law is made, then it is a serious matter. I do not know whether the authorities consulted Mr. Om Mehta or Mr. Brahmananda Reddy for that matter. But when an MLA is picked up and arrested over an issue of this type, which is a public issue, it is the duty of Central Government to make inquiries, and I do hope that Mr. Om Mehta will kindly tell us what the position is. He is known to Mr. Garg, I believe. You know Mr. Garg? You do not know him? Anyway, you better find out. He is very well known. Madam Vice-Chairman knows him very well. Many of you know him in fact, the Prime Minister knows him very well. Other Ministers know him very well, and your Congress President also knows him very well. We all know him very well. He had made a lot of contribution in the fight against privy purse and so on. How is it that such a man, when he comes to ventilate the workers' feeling against sell-out of the public sector undertaking by Mr. Pai and to emphasise that the Prime Minister's assurance to the Heavy Electricale workers at Hardwar should be fulfilled, should be arrested? I think you will share my indignation over such a kind of thing. This is becoming a very common practice. I protest against the arrest of Mr. Garg and others. I do hope that the UP Assembly would take this up in a fitting manner and we shall take up his and the workers' case. I do hope that Mr. Pai will come and state here the position. It is the duty of the Prime Minister to tell us whether she gave such an assurance to the Heavy Electricals workers at Hardwar and if so, why that assurance is allowed to be violated by one of her Cabinet colleagues, Mr. T. A. Pai. The position should be clarified by both the Prime Minister and Mr. Pai. Anyhow, all I can say is that Mr. Garg and others should be set free immediately.